

SHRI PILOO MODY : What is the use of having just a discussion about these matters ? I am sure the House has discussed this many times. The point is whether some action can be taken in the matter.

— — —

12.43 hours.

PAPER LAID ON THE TABLE

Annual Report and Accounts of  
Export Inspection Council

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : I lay on the Table a copy of the Annual Report of the Export Inspection Council for the year 1967-68 along with the audited accounts. [Placed in Library. See No. LT-589/69]

— — —

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

Fifth-ninth Report

SHRI M. R. MASANI (Rajkot) : I present the Fifty-ninth Report of the Public Accounts Committee on Audit Report (Civil), 1968, relating to the Cabinet Secretariat (Indian Statistical Institute).

— — —

12.44 hrs.

STATEMENT UNDER DIRECTION 115

Removal of Control on Prices of  
B. Twill Bags

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे अतारंकित प्रश्न संख्या तीन हजार सात सौ

पन्द्रह का 19 मार्च, 1969 को वैदेशिक व्यापार मंत्री ने जो उत्तर दिया वह असत्य भाषण और गलत बयानी की एक गुत्थी है। इस दलील में कोई दम नहीं कि यह गलत उत्तर कबिना के मंत्री ने नहीं बल्कि वैदेशिक व्यापार मंत्रालय के उप-मंत्री ने दिया।

मैं मन्त्री महोदय से मांग करना चाहता हूँ कि वह अपने गलत बयान को सुघारें, सदन से खेद प्रकट करें और बी-टिवल बैंग्र की बोरों की खरीदी को लेकर सरकार तथा निम्न सरकारी एजेंसियों और फुड कारपोरेशन आदि का जो एक करोड़ सत्तासी लाख रुपये का घाटा होने वाला है उस को तत्काल कार्यवाही कर के बचायें।

मैंने सरकार से पूछा था कि क्या बी-टिवल बोरों का दाम नियंत्रण हटाने का सरकार का इरादा है ? मन्त्री महोदय ने कहा कि इस तरह का कोई सुभाव उन के सामने नहीं है। यह सही नहीं है। असल में वैदेशिक व्यापार मन्त्री इस सुभाव पर विचार कर रहे थे, लेकिन मेरे 3 मार्च, 1969 के पत्र के आधार पर वित्त मन्त्रालय ने इस में जो दखल दी उसी को लेकर दाम नियंत्रण को हटाने का सुभाव फिलहाल रद्द कर दिया गया है।

मैंने सरकार से यह भी पूछा था कि उन का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि बिरला और के० पी० गोयंका आदि जूट मिलों के गुट इस आशा से बी-टिवल बोरों की जमाखोरी कर रहे थे कि दाम नियंत्रण हटाने पर उनको ज्यादा मुनाफा मिलेगा ?

मन्त्री महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं, उनका ध्यान नहीं दिलाया गया है। लेकिन यह भी सही नहीं है क्योंकि 3 मार्च, 1969 के मेरे खत में मैंने उपप्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री के सामने यह बात लाई थी कि दो सौ चालीस